अमर उजाला, शिमला, चंडीगढ़, 24 अप्रैल, 2008

कार्यदल के गठन की वकालत

एनजीओ के लिए बने राज्य नीति

अमर उजाला ब्यूरो

कवायद

राज्य नीति के लिए स्वयं सेवी संगठनों की पहल

शिमला। स्वयं सेवी संगठनों के लिए राष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर राज्य में भी नीति बननी चाहिए। बुधवार को राजधानी के वाईएमसीए में राज्य भर से आए विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों ने इस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन स्वयं सेवी संगठन वाणी, ईरा और माउंटेन फार्म द्वारा मिलकर किया गया। राज्य भर से आए करीब 40 स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इस मौके पर पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक डॉ राजीव बिंदल के मार्कंडेय ने राष्ट्रीय नीति का स्वागत कर स्वयं सेवी संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की।

रणनीति : शिमला के वाईएमसीए में वाणी संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लेते लोग।

उन्होंने कहा कि अगर संगठन राज्य नीति तैयार करते हैं तो वह मुख्यमंत्री से इसकी सिफारिश करेंगे। इस मौके पर वाणी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परेश तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय नीति में निजी संस्थाओं को चिन्हित किया गया और उनकी स्वायत्तता का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि राज्य सरकार गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर राज्य नीति तैयार करे। ईरा के निदेशक प्रदीप शर्मा ने भी कार्यशाला में राज्य नीति बनाने के लिए अपने विचार रखे।

राज्य नीति बनाने के लिए कार्यशाला के अंत में सात सदस्यीय कार्यदल का गठन भी किया गया। इस दल में अरुण चंदन, आनंद शर्मा, अजय श्रीवास्तव, विश्व प्रेमी, पीआर रमेश, सुशील कुमार और नरेन्द्र शामिल हैं। यह दल स्वयं सेवी संगठनों के लिए राज्य नीति का खाका तैयार कर इसे सरकार को सौंपेगा। यह दल वीरवार को सामूहिक बैठक का आयोजन कर राज्य नीति के खाके की तैयारियों से संबंधित चर्चा करेगा।

दैनिक जागरण. हिमाचल धर्मशाला, 24 अर्पेल, 2008

'नेशनल पॉलिसी ऑन वालंटरी सेक्टर' पर मंथन

- स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का सेमिनार आयोजित
- सरकारी संगठनों की विकास में अहम भूमिका : मार्कंडेय
- आपदाओं में कर रहे हैं बेहतरीन कार्य

संवाद सहयोगी, शिमला : प्रदेश में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का एक सेमिनार वाईएमसीए हाल में आयोजित किया गया। सेमिनार का आयोजन वानी (वीएएनआई), ऐरा (ईआरए), एमएफएच द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 'नेशनल पॉलिसी ऑन वालंटरी सेक्टर' पर मंथन किया गया। सम्मेलन में लाहुल-स्पिति जिले के विधायक रामलाल मार्कंडेय मुख्यातिथि थे।

इस अवसर पर मार्कंडेय ने कहा कि गैर सरकारी संगठनों की देश के विकास में अहम भूमिका है। ये संगठन उन क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं जहां सरकार नहीं पहुंच सकती है। स्वैच्छिक संगठन एड्स नियंत्रण, टीबी नियंत्रण कार्यक्रमों तथा प्राकृतिक आपदाओं में बेहतर कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे संगठनों के स्वेच्छा से काम करने वाले सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। मार्कंडेय ने कहा कि आज समय आ गया है कि स्वैच्छिक संगठन कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में अपनी भूमिका निभाएं। इससे किसानों को लाभ होगा साथ ही कृषि की तकनीक में सुधार आएगा। वानी संस्था के मुख्य कार्यकारी परेश तिवारी ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं को बेहतर कार्य करके समाज के निर्माण में अपनी भूमिका प्रभावी तौर से निभानी चाहिए। इससे एक बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है।

ऐरा संस्था के निदेशक प्रदीप शर्मा, माउंटेन फोरम हिमालया संस्था के सचिव डा. अरुण चंदन ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान स्वैच्छिक संगठनों की कार्यप्रणाली, सरकारी कार्यों में संगठनों की सहभागिता इत्यादि मुद्दों पर चर्चा की।

दिव्य हिमाचल, शिमला, 24 अप्रैल 2008

शिमला : स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय नियम बनाने को लेकर आयोजित सम्मेलन में भाग लेते विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि

हिमाचल भास्कर, चंडीगढ़, वीरवार 24 अप्रैल, 2008

परामर्श कार्यक्रम में जुटे स्वयंसेवक

भास्कर न्यूज़. शिमला

वॉलयंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी) और सोसायटी फॉर इंवायर्नमेंट रूरल अवेकनिंग (ईरा) और माउंटेन फोरम हिमालय (एमएफएच) ने कार्यशाला का आयोजन किया। वाईएमसीए में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए बनाई गई राष्ट्रीय योजना के बारे में चर्चा की गई। राज्य भर से आए स्वयं सेवियों को केंद्र सरकार की वर्ष 2007 में बनाई गई 'नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलयंटरी सेक्टर' की जानकारी दी गई। इस अवसर पर लाहौल-स्पीति के विधायक राम लाल मार्कंडेय बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए। ईरा के निदेशक प्रदीप शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में एनजीओ के कार्यकर्ताओं से राज्य योजना बनाने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। कार्यशाला में पांच सदस्यीय समूह का गठन किया गया।

वाईएमसीए में राष्ट्रीय योजना की कार्यशाला में भाग लेते विधायक रामलाल मारकंडे।

क्या है राष्ट्रीय योजना

योजना आयोग के वॉलयंटरी एक्शन सैल ने स्वयं सेवी संस्थाओं को स्थापित करने, विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने वाली कॉम्युनिटी बेस्ड, एनजीओ, चैरीटेबल संस्थाओं को समर्थन देना। पॉलिसी को छह भागों में बांटा गया है।